

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024—श्रावण 18, शक 1946

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (1989), मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 6-16/2012/एक/1.—विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1302/1931/XXI-B/C.G./2024, दिनांक 27 जून, 2024 द्वारा श्री सुधीर कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की सेवाएँ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से वापस लेते हुए, प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है।

2. राज्य शासन एतद्वारा श्री सुधीर कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जून 2024

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 25-10-2017, अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 03-01-2018, अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 27-03-2018 एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 21-08-2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीकृत किया गया था।

राज्य शासन एतद्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है :—

क्र.	शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता	बाल गृह का पता	जिला	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
1.	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह	कन्या परिसर रोड़, गंगापुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	सरगुजा	सम्प्रेक्षण गृह (बालिका)	—	25	06/SRG/17-18
2.	शासकीय विशेष गृह (बालिका)	कन्या परिसर रोड़, गंगापुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	सरगुजा	विशेष गृह (बालिका)	—	25	07/SRG/17-18
3.	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	न्यू जी.ए.डी कॉलोनी, पानी टंकी के पास, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)	दन्तेवाड़ा	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50	—	06/DNTWD/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.
3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.
4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जून 2024

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-01/2023/मबावि/50, नवा रायपुर दिनांक 06-12-2023 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीयन का नवीनीकरण किया गया है.

राज्य सरकार एतद्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्न संस्था में आंशिक संशोधन करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है :—

क्र.	शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता	बाल गृह का पता	जिला	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
1.	मानव संसाधन संस्कृति विकास परिषद्, सरस्वती कुंज, जोड़ा टावर के पास, दर्रीपार, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	सरस्वती कुंज, जोड़ा टावर के पास, दर्रीपार, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	सरगुजा	बालगृह (बालिका)	—	50	02/SRG/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा.
2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.
3. संस्था द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.
4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 10 जुलाई 2024

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/9997/भू-अर्जन/2024. — भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का भू-अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कटघोरा	जटांगपुर	4.652 हे.	जटांगपुर एनीकट योजना के डूबान क्षेत्र हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24-07-2024 को समय 02.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, पंडरीपानी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जटांगपुर एनीकट योजना के डूबान क्षेत्र हेतु
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या —	—	06 परिवार
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
8	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 317.53 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से 25 हे. में खरीफ सिंचाई सुविधा उद्बहन सिंचाई द्वारा (स्वयं के खर्च पर) उपलब्ध कराई जावेगी.
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2024

प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-कारीछापर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.310 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/1	0.129
16/1	0.162
4/2	0.440
16/3	0.028
5/2	0.081
16/2	0.405
5/4	0.065
योग	7
	1.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग संभाग धरमजयगढ़ को परियोजना अंतर्गत कारीछापर एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2024

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-घरघोड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.782 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110/1	0.214
150/2	0.115
110/2	0.250
110/3	0.093
110/4	0.110
योग	05
	0.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग संभाग धरमजयगढ़ को परियोजना अंतर्गत कारीछापर एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कायाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2024

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2024-25/1904.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2023-24/6060-6061 रायपुर दिनांक 15-12-2023 द्वारा श्री एल.एल. नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बागबाहरा, जिला-महासमुंद को कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था।

कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा के भारसाधक अधिकारी श्री एल.एल. नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बागबाहरा, जिला-महासमुंद, दिनांक 29-02-2024 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने से उनके स्थान पर श्री गंगा प्रसाद शरणागत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) बागबाहरा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री एल.एल.नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बागबाहरा, जिला-महासमुंद के स्थान पर श्री गंगादास शरणागत, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) बागबाहरा को कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा, जिला-महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

महेन्द्र सिंह सवनी,
संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 21st June 2024

No. 590/Confdl./2024/II-2-90/2001 (Part-IV).—Shri Pankaj Kumar Jain, Member of Higher Judicial Service and presently posted as District and Additional Sessions Judge, F.T.S.C. (POCSO), Dhamtari is transferred and appointed as Registrar (Selection & Appointment) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 21st June 2024

No. 592/Confdl./2024/II-2-90/2001 (Part-IV).—Shri Aditya Joshi, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Officer-on-Special Duty in the establishment of this High Court is, hereby, directed to render his services as Member of the Editorial Board under the e-Law Reports Committee, in addition to his own duties, till further orders.

By order of the High Court,
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General.